



Neutral Citation No. -

2026:AHC:64684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या – 2227 वर्ष 2026

अकबर अली

.....आवेदक बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनीश कुमार सिन्हा, मनोज कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 547/2025, धारा 69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- गोरखनाथ, जिला गोरखपुर के तहत दायर की गई है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपरोक्त मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि आवेदक ने कभी भी विवाह का कोई झूठा वादा नहीं किया है। पीड़िता एक विवाहित महिला है, जिसके चार बच्चे हैं और अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, उनका तर्क है कि विवाह का कोई वादा नहीं किया जा सकता जब विवाह निषिद्ध है। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कराते समय अपनी वैवाहिक स्थिति को छिपाया है। उनका आगे तर्क है कि कथित पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ कमांडेंट, 26वीं बटालियन एसएसबी, रांची, झारखंड के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जहां आवेदक उस समय कार्यरत था, और वहां के डिप्टी कमांडेंट, जो जांच अधिकारी भी थे, ने एक तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 14 में उल्लेख किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता को आधार विवरण में हेरफेर करने का आरोपी पाया गया था और वह अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक की पत्नी ने धारा 173(4) BNSS के तहत आवेदन दाखिल करके मुखबिर के खिलाफ धारा 319(2), 318(4), 351(3), 352, 308(3), 131 BNS के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 343/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है। आवेदक सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल जीडी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

5. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने अग्रिम जमानत की अर्जों का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक ने विवाह का झूठा वादा किया और शिकायतकर्ता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि पीड़िता एक विवाहित महिला है जिसके चार बच्चे हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

7. पीड़िता विवाहित महिला बताई जा रही है और उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। उसके चार बच्चे हैं। पीड़िता के खिलाफ आवेदक की पत्नी द्वारा महाराजगंज में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जांच में, जिसका एक हिस्सा पैराग्राफ संख्या 14 में उद्धृत किया गया है, यह प्रतीत होता है कि पीड़िता ने 26वीं बटालियन, एसएसबी के कमांडेंट के समक्ष आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने का दावा किया है। शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 14 की सामग्री को विद्वान एजीए द्वारा प्राप्त टिप्पणियों में अस्वीकार नहीं किया गया है।

8. एसएसबी द्वारा की गई जांच, एफआईआर में दर्ज बयानों और पीड़िता के विवाहित महिला होने के बीच विरोधाभास को देखते हुए, प्रथम दृष्टया धारा 69 बीएनएसएस के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इस आधार पर, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

10. आवेदक अकबर अली की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और एक निजी मुचलका प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

28 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

ए. पांडे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"